



Neutral Citation No. - 2026:AHC:37184

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2491/2026

दिनेश चंद्र खरे

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आशुतोष मिश्रा, सैयद आबिद अली नकवी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष मिश्रा और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय की दलीलें सुनी गईं।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि उसे 23.02.1974 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था और वह 03.12.2008 को सेवानिवृत्त हो गया था, फिर भी उसे 6वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, 24.08.2009 के सरकारी आदेश के तहत एनपीए का 25% नहीं दिया गया है; साथ ही, उसे 24.08.2009 से 09.03.2019 तक की संशोधित पेंशन का बकाया भी नहीं मिला है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय चौथे प्रतिवादी-निदेशक पेंशन, पेंशन निदेशालय, इंदिरा भवन, लखनऊ-द्वारा किया जाएगा।
4. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इन दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता 27.02.2026 तक, इस रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, एक विस्तृत अभ्यावेदन चौथे प्रतिवादी-निदेशक पेंशन, पेंशन निदेशालय, इंदिरा भवन, लखनऊ-के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके बाद, चौथा प्रतिवादी दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

19 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”